यह बात सही कि गोलकनाथ केस के बाद और बैंक नेशनलाइजेशन के केस के बाद अब राष्ट्रीयकरण करना मेरी दृष्टि से तो बिलकुल असंभव हो गया है क्योंकि राष्ट्रीयकरण के लिए दुगुना, तीन गुना अगर मुआवजा देना है और सो भी कैश के रूप में देना है तो इसका मतलब होगा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक समानता प्रस्तावित करने के लिए अब सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना बिलकुल बेमतलब हो जाता है। इसलिए दरमियानी रास्ते के लिए मेरा सुझाव है कि संविधान में कुछ हम लोग परिवर्तन करें और ईमानदारी से करें। इस तरह की जो एक बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है या हम श्रेष्ठ हैं यह बेमतलब है। आप संविधान में कौन-सा परिवर्तन चाहते हैं यह सदन के सामने रखिए और इन परिवर्तनों को लाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग सोचें।

जहां तक सम्पत्ति का सवाल है सम्पत्ति के बारे में 19 वीं धारा में एफ और जी और साथ-साथ 26 वीं धारा में सी और डी और 31, 31-ए और 31-बी, 31-बी में तो कोई खराबी नहीं है इसलिए उसको तो मैं छोड़ देता हूं लेकिन 31, 31-ए, 26 सी और डी और 19 एफ और जी, इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने स्वयं इसके बारे में कई विधेयक दिए हैं। लेकिन जो ताजा विधेयक मैंने दिया है उसमें मैंने चाहा है कि 19 एफ और जी को हटा दिया जाय, 26 सी और डी को हटा दिया जाय और 31 ए में जहां एस्टेट शब्द का प्रयोग है वहां पर "आर प्रापर्टी" जोड़ दिया जाय ताकि जमीन और भूमि-सुधार के अलावा जो कारखाने वाली सम्पत्ति है वह भी इसमें आए क्यों कि इस संविधान का आधार है पूंजीवादी। इस संविधान में जो परिवर्तन किए गए वह भूमि सुधार के लिए या सामन्ती अधिकारों को समाप्त करने के लिए, पूर्णतया नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में लेकिन जो पूंजीवादी अधिकार हैं यानी शहरी सम्पत्ति जो है कारखानों की सम्पत्ति जो है उसके अधिकारों के बारे में संविधान बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। तो मैं यह चाहूंगा कि जिस स्तर पर आपने एस्टेट को रखा है उसी स्तर पर अन्य सम्पत्ति को भी ले आइए ताकि पूंजीवाद के बारे में कोई रियायत दिखाने की बात न हो। जो जमींदारी आदि के बारे में रवैया रहा वही पूंजीवाद के बारे में हो। अब रह जाती है संविधान की धारा 31। तो उसमें ..... **(व्यवधान)**...... वह बता रहा हूं। जो एस्टेट के लिए है, जमीन के लिए है, मैं यह कह रहा हूं कि 31-ए एम एस्टेट लिखा हुआ है उसमें प्रापर्टी भी जोड़िए ताकि शहरी सम्पत्ति भी उसमें आए। उसमें क्या आपत्ति आपको हो सकती है? अब जहां तक किसानों की जमीन का या छोटे लोगों की सम्पत्ति का सवाल है मैंने 31 वीं धारा को बदलना चाहा और मैंने यह कहा है कि:

> "No person holding or possessing property below the ceiling prescribed by law in this behalf. ......"

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे। अब हाफ ऐन अवर डिस्कशन शुरू होगा।

श्री मधु लिमये:

> "No person holding or possessing property below the ceiling prescribed by law in this behalf and which shall not exceed..."

MR. DEPUTY SPEAKER: He can continue the next day.

18.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

HELP TO FOOD CORPORATION OF INDIA BY NATIONALISED BANK

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा 23 फरवरी को दिये गये

[श्री भोगेन्द्र झा]

एक सवाल के उत्तर के आधार पर पैदा हुई है। इस सवाल में पूछा गया था कि खाद्य निगम को और अधिक वित्तीय सहायता सरकार देने जा रही है या नहीं, जिससे कि ज्यादा गल्ले का स्टाक जमा किया जा सके और देश में गल्ले की जो कीमत बढ़ती है या बढ़ने का खतरा रहता है, उसको रोका जा सके। उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि उसके लिये 200 करोड़ रुपये की जो सीमा तय को गई थी, उस हद से आगे बढ़ने भारत सरकार नहीं जा रही है और खाद्य निगम के लिये एक भी पैसा फाजिल बढ़ाने के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अवधि में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं, लगभग समूचे देश में बढ़ी हैं और खास कर आपके जरिये मैं वित्त मंत्री जी को बता दूं कि उत्तर बिहार के उन हिस्सों में जो अभावग्रस्त हैं और जिनके बारे में सरकार ने स्केअरसिटी एरिया का ऐलान किया है, वहां भी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वहां भुखमरी की हालत पैदा हो गई है।

पिछले दिनों, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है देश के अन्दर सामाजिक नियन्त्रण का एक ढकोसला रचा गया था जिसमें कहा गया था कि बैंकों के ऊपर एक हद तक नियन्त्रण रखा जायगा ताकि मुनाफाखोरी के लिये, चोर बाजारी के लिये जो रुपया अग्रिम के रूप में व्यापारियों को दिया जाता है, उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन हुआ क्या ? एक तरफ तो अपने जवाब में ये कहते हैं कि हम खाद्य निगम को अनाज की खरीद के लिये 200 करोड रुपये से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये मैं सदन को बतलाना चाहता हूं—राष्ट्रीयकरण होने से देश को कम से कम इस मामले में कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वे बैंक अभी भी बड़े-बड़े व्यापारियों, बड़े-बड़े मुनाफाखोरों के हुकम में चल रहे हैं, उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सके हैं ?

एक दूसरे तारांकित प्रश्न सं० 835 के उत्तर में जो 6 अप्रैल को पूछा गया था, इन्होंने कबूल किया है कि 1969 में 31 अक्तूबर तक स्टेट बैंक की ओर से 805 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया था, 31 मार्च, 1970 तक 880 करोड़ रुपया दिया गया, यानी 3 महीने की अवधि में 75 करोड़ रुपया फाजिल दिया गया.........

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : किसको दिया है।

श्री भोगेन्द्र झा : बड़े-बड़े मुनाफाखोरों को दिया है। यह आपके 6 अप्रैल के जवाब से स्पष्ट है। जो दूसरे स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक हैं—उन्होंने 62 करोड़ रुपया फाजिल दिया है। जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने 241 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद 304 करोड़ रुपया दिया—यानी 62 करोड़ रुपया ज्यादा दिया। इसी तरह से जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं—उन 14 बैंकों के जरिये राष्ट्रीयकरण से पहले 1841.9 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद 13 मार्च तक 2119 करोड़ रुपया दिया गया, यानी 277.4 करोड़ रुपया फाजिल दिया गया। यदि आप इन सबको जोड़ लें तो आपको मालूम होगा कि कुल मिला कर 414.6 करोड़ रुपया फाजिल दिया गया। जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उस समय तक इन सब बैंकों के द्वारा 2,889.5 करोड़ दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद 3304.7 करोड़ दिया गया, इस तरह से

414.6 करोड़ रुपया फाजिल दिया गया। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि देश के अन्दर जो मंहगाई बढ़ी है, उसके लिये यह सरकार दोषी है और इन्होंने मेरे ही 30 मार्च के एक प्रश्न के उत्तर में कुबूल किया है कि बैंकों के अग्रिम रुपया देने से मंहगाई बढ़ी है और अब ये उस पर लगाम लगाने जा रहे हैं। कुछ कदम हाल में उठाये भी हैं, रिजर्व बैंक की शर्तों को कुछ कड़ा भी किया है।

लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आपके अन्दर हालत सुधारने की ताकत नहीं है, तो आपने पहले से ही यह एलान क्यों किया कि आप एक पैसा भी खाद्य निगम को फाजिल देने नहीं जा रहे हैं। आपकी इस घोषणा का व्यापारियों पर असर पड़ा और मंहगाई और ज्यादा तेजी से बढ़ी। इसका क्या नतीजा होगा देश के अन्दर मंहगाई भत्ते की मांग उठेगी, दूसरी मांगें पैदा होंगी और जब आप उनको पूरा नहीं कर सकेंगे तो हड़तालें होंगी, आपको लाठी और गोलियों का इस्तेमाल करना होगा। आज किसानों के हाथों से धान की फसल बहुत सस्ते दामों पर मुनाफाखोरों के हाथों में चली गई है, क्योंकि उनके पास बैंकों से बहुत बड़ी रकम अग्रिम के रूप में पहुंच गई है। आप कहते हैं कि बैंकों से कितना अग्रिम देते हैं, उस पर कीमत निर्भर नहीं करती है। यह ठीक है कि किसी चीज की कीमत का सस्तापन या मंहगापन उसपर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो 414 करोड़ रुपया आपने फाजिल दे दिया, उसका गल्ला अगर बैंकों के गोदामों में बन्द हो जाय तो उसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा, कन्ज्यूमर या खरीदार तो बैंकों के गोदामों में बन्द नही हुआ है, उसे तो खाने को चाहिये, यहां मार्शल और स्मिथ का डिमाण्ड और सप्लाई का सिद्धान्त लागू हो जाता है। माल कम हो जायगा और खरीदनेवाले ज्यादा होंगे, तो मंहगाई बढ़ेगी। इस तरह से कृत्रिम रूप से जो मंहगाई पैदा की जा रही है—जो गल्ला देश के बाजारों में आता है, बैंक से रुपया लेकर, जनता के उस रुपये से कुछ मुनाफाखोर किसानों से सस्ते दामों पर खरीद कर बैंक के गोदामों में जमा कर देते हैं और जब बाजार में गल्ले का भाव बढ़ जाता है, कृत्रिम रूप से मंहगाई पैदा कर के, फिर उसी किसान को, शहर के लोगों को, मजदूरों को उसी गल्ले को महंगे दामों पर बेचते हैं, इस तरह से देश की जनता को लूटते हैं।

हमारे देश में यह जो मुनाफाखोरी का रिवाज है, लूट और खुली डकैती का रिवाज है, इसमें भारत सरकार भी शामिल है, बैंकों के मालिकान शामिल हैं, वित्त विभाग शामिल है—जब कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इस लिये मेरा आग्रह है कि इसमें भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये। सबसे पहले तो यह देखना चाहिये कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है, किसने ऐसा किया है कि इन चार-पांच महीने में पिछले साल के मुकाबले इतना ज्यादा रुपया अग्रिम के रूप में व्यापारियों को दिया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय प्रधान मंत्री जी ने कहा था इस रुपये को देश की जनता के हित में खर्च किया जायगा। हमने आशा की थी कि कम से कम मुनाफाखोरों, चोर-बाजारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पहले के मुकाबले कम पैसा दिया जायगा, बल्कि दिया ही नहीं जायगा, लेकिन वह कम नहीं हुआ, जितना पहले दिया गया था, उससे भी ज्यादा दिया गया, 414 करोड़ रुपया ज्यादा दिया गया, जिससे इन लोगों ने देश की मंहगाई को बढ़ा दिया, लोगों की जेबों पर हमला किया। इस लिये क्या आपकी सरकार इस बात की जांच कराने जा रही है कि वित्त मंत्री के आदेश से या प्रधान मंत्री के आदेश से या किसके आदेश से ऐसा काम हुआ

[श्री भोगेन्द्र झा]

है या रिजर्व बैंक के अधिकारियों, स्टेट बैंक के अधिकारियों या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की मर्जी से ऐसा हुआ है। अगर इन लोगों ने अपनी मर्जी से ऐसा किया हैं तो क्या आप जांच करवा कर इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं जिन्होंने 50 करोड़ देशवासियों की जेब पर हमला किया है ?

दूसरी बात—जो अग्रिम दिया गया है और अब आप शर्तों को कड़ा करने जा रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आप उन थोक व्यापारियों को कहेंगे— खास कर खाद्यान्न के थोक व्यापारियों को कि जो रुपया उनको बैंकों से मिला हुआ है, उसको वे वापस कर दें। अगर उन को रुपया वापस करने के लिये मजबूर किया जायगा, तो गल्ला बाजार में आ जायगा, इससे मंहगाई बढ़ने नहीं पायेगी। अगर सस्ता न हुआ तो कम से कम राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जितना फाजिल रुपया उन्होंने लिया हुआ है, उसका माल उनको बाजार में लाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

तीसरी बात—जो गल्ला खरीद हो गया है, क्या इसके लिये सरकार ने यह कदम उठाया है या बैंकों ने यह कदम उठाया है कि पूरे साल भर में उनकी कीमत नहीं बढ़ने दी जायगी। चूंकि आम तौर से हमेशा यही होता आया है कि धान की, गेहूं की फसल के वक्त बाजार मन्दा कर दिया जाता है। पिछले साल का मुझे मालूम है कि बैंकों ने अग्रिम देना बन्द कर दिया था और 59, 60 रु० क्विन्टल के हिसाब से किसान का माल खरीद कर लूटा गया और उसके बाद फिर बैंकों ने अग्रिम दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि चार, पांच महीने बाद वही गेहूं 118 रु० क्विन्टल तक गया। तो इस तरह से जो लूट हो रही है, जो किसान को उसकी उपज का उचित पैसा नहीं मिल रहा है, उपभोक्ताओं को दुगना दाम देना पड़ता है और बीच का तबका लूटता है जिसमें बैंक सहायक होता है, ऐसी स्थिति में आप कौन सा कदम उठाने की सोच रहे हैं ताकि यह लूट रोकी जा सके, और जिस दर पर किसानों का गल्ला खरीदा गया है साल भर तक उससे आगे दाम नहीं बढ़ने देंगे ? जो मुनासिब सूद की दर हो, चाहे ढोने का भाड़ा हो या मकान में रखने का दाम हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई दर आप तय करें कि साल भर में इससे ज्यादा कीमत न बढ़ने पाये।

चौथा सवाल यह है कि खाद्य निगम पर और सरकार पर बड़े-बड़े थोक व्यापारियों का असर अभी भी मौजूद है। यह ठीक है कि उनका एक हिस्सा अभी खिसक कर उधर से इधर आ गया है, लेकिन अभी भी इनके बैंकों पर, सरकार पर, मंत्रिमंडल पर और सम्बन्धित अधिकारियों पर उनका असर हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि खाद्यान्नों में थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो सके। उसमें कोई बहुत बड़ी कीमत का सवाल नहीं उठेगा, उसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें कोई सम्पत्ति आप नहीं ले रहे हैं। खुदरा व्यापार आप छोड़ दें, उसकी मैं बात नहीं करता, मगर थोक व्यापार क्या आप अपने हाथ में लेने जा रहे हैं ? और अगर नहीं तो उसके क्या कारण है ? और अब तो पैसे की कमी का भी कोई कारण नहीं है बैंकों के आपके हाथ में आ जाने के बाद। एक तरफ खाद्य निगम थोक व्यापार करता है, और दूसरी तरफ बड़े-बड़े व्यापारी थोक व्यापार करते हैं। आपने खाद्य निगम के लिये तो बैंकों से अग्रिम देने के लिये एक हद तय कर दी है कि 200 करोड़ रु० से ज्यादा आप उसको नहीं देंगे। लेकिन थोक व्यापारियों

के लिये कोई हद नहीं है। वह घूस देकर जितना चाहें ले सकते हैं, लेकिन खाद्य निगम की तरफ से कौन घूस देगा। जिस मामले में खाद्य निगम के अधिकारी गल्ला खरीदने के लिये आते हैं तो थोक व्यापारी और उनका संगठन खाद्य निगम के अधिकारियों को प्रभावित करके उन्हें बाजार में नहीं जाने देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि किसान मनमाने ढंग से इन व्यापारियों द्वारा लूटे जाते हैं। इस प्रकार खाद्य निगम के अधिकारी थोक व्यापारियों के हाथ में बैठे हुए हैं। इसका एक स्पष्ट प्रमाण मैं देता हूं कि तीसरे साल बिहार का जूट जब बाजार में आया तो उसकी केवल एक फीसदी की खरीद हुई क्योंकि खाद्य निगम के जूट केन्द्र में जो अधिकारी बैठा हुआ है वह दोहरा मुसहरा पाता है—भारत सरकार से भी और थोक व्यापारियों की तरफ से भी। परिणाम यह हुआ कि किसानों ने जूट की खेती छोड़ दी, और सरकार को विदेशी जूट मंगा कर मिलों को देनी पड़ी। इस प्रकार की सांठगांठ चलती है। इसलिये मेरा कहना है कि जब तक खाद्य निगम भी रहेगा और थोक व्यापारी भी रहेंगे, तो खाद्य निगम थोक व्यापारियों का मुकाबला नहीं कर सकेगा क्योंकि व्यापारी घूस के जरिये से, चोरी करके जो काला धन जमा किया है उस के जरिये वह खाद्य निगम के अधिकारियों को अपने हित में प्रभावित करते रहते हैं जिसकी वजह से खाद्य निगम उनका मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिये मेरा आगृह है कि भारत सरकार इस बात पर विचार कर थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की ओर कदम बढ़ाये।

माननीय जगजीवन राम ने जवाब दे दिया है, हम जानते हैं कि उनको बड़े थोक व्यापारियों के लिये ममता है, यह समझते होंगे कि जब उनके यहां थैली जायगी तो इनके यहां कुछ नहीं आयेगी, इसलिये बड़े व्यापारियों के लिये मुरव्वत, दिखाना चाहते हैं, जान बचा कर काम करें, ताकि कुछ पैसा मिल जाय। इसीलिये यह कोई कदम उठाने में हिचक रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो महंगी बढ़ रही है इनके खिलाफ देश आन्दोलन करेगा। जनता चुपचाप नहीं बैठेगी। मार्च अप्रैल के बाद मुझे खतरा है कि महंगी बढ़ेगी। इसलिये अगर आप ने महंगी पर लगाम नहीं लगायी तो हड़तालों का नया तांता शुरू होगा। अभी पुरानी हड़तालों के लिये जो आप ने कार्यवाहियां की थीं, थोड़ा थोड़ा करके उनको खत्म करने की आप ने कोशिश की है। लेकिन अगर आप ने महंगी को नहीं रोका तो हड़तालों का फिर से तांता शुरू हो जायगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि आप थोक व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करें। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में कोई विचार कर रहें हैं कि नहीं ? मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें। अगर सरकार ने अभी कोई स्पष्ट राय नहीं बनायी है, तो सरकार इस पर विचार करे। नहीं तो अगला खतरा आने वाला है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप ने कर लिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा। जब तक बैंक चोर व्यापारियों के हाथ में रहेंगे तब तक देश शान्त नहीं होगा, बड़ा संघर्ष छिड़ने वाला हैं, बड़ा संघर्ष आने वाला है। सरकार को थोक व्यापार का शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मान्यवर, मेरे चार सवाल हैं। पहला यह कि फूड कारपोरेशन द्वारा बफर स्टाक बनाने के लिये कर्ज के रूप में या पैसे के रूप में पी० एल०480 से कितना रुपया मिलता है ?

[श्रीशिव चन्द्र]

दूसरा मेरा सवाल यह है कि पांच मिलियन जो इस साल के लिये स्टाक बनाने की बात है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हकीकत में हमारी कितनी जरूरत है ? जो स्टाक आप बना रहे हैं, वह कितना है और जरूरत कितनी है ?

तीसरा सवाल यह है कि बफर स्टाक बनाने से कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा। क्या आपने नेशनेलाइज्ड बैंक्स द्वारा ट्यूब वेल्स, पम्पिंग सेटस और बोरिंग के लिये देहातों के लिये आम सहूलियत की कंडीशन पर कोई योजना कर्ज देने की बनायी है ? यदि हां तो वह क्या योजना है ?

और चौथा सवाल यह है कि क्या सरकार होल सेल ट्रेडिंग इन फूड को नेशनेलाइज करेगी ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा पहला सवाल उपाध्यक्ष जी, यह है कि किसान को बचाने के लिये, उसको अपने माल की कम कीमत न मिले जिस वक्त वह अपना अनाज मंडी में लाये, क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि देहात में या आसपास के कस्बों में ग्रैन बैंक्स खोले जायें जहां किसान लोग अपना अनाज दे दें और उनके पास पास बुक हो, कुछ पैसे उनको फौरन दे दिये जायें और फिर साल भर की कीमत का ऐवरेज लगा कर उनको पैसे दे दिये जायें। ऐसी कोई चीज आपके ध्यान में है ? कांग्रेस में भी यह बात पेश हुई थी।

दूसरी बात यह है कि क्या आप कोई ऐग्रीकल्चर क्रेडिट कोरपोरेशन किसान को, छोटे किसान को, देने के लिये खोलने की कोशिश कर रहे हैं ? अमीर किसान तो ले जाते हैं, लेकिन गरीब किसान के लिये, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोरपोरेशन है, इस किस्म की कोई संस्था, ऐग्रीकल्चर क्रैडिट कोरपोरेशन खोलने की कोशिश कर रहें हैं ताकि वे बनियों के हाथ में न फसें ?

तीसरी चीज यह है कि जो बैंकों के बोर्डस हैं उनमें किसान रिप्रेजेन्टेटिव्ज को लेने की बात आपने कही थी। लेकिन उन का कोई रिप्रेजेन्टेटिव मुझे नजर नहीं आता। क्या आप हर लेविल पर किसान रिप्रेजेन्टेटिव को उस बोर्ड में लेंगे, और जो बैंकों की पूंजी है उसका 70 परसेंट, 60 परसेंट या 55 परसेंट, किसानों को देने के लिये कोई परसेंटेज मुकर्रर करेंगे, क्योंकि उनकी 80 फीसदी आबादी है। इसलिये कुछ परसेंटेज आप मुकर्रर करेंगे कि इतना पैसा छोटे किसान को मिलेगा ?

और आखिरी बात यह कहनी है कि सरकार सारे फूड ग्रेन्स की ट्रेड को अपने हाथ में ले ले। एफ० सी० आई० एक तरह से मनी लेंडर बन गया है, सारी ग्रेन्स बैंक वाले रख लेते हैं, इस लिये किसान को बचाने के लिये फूड ग्रेन्स को नेशनेलाइज करने की बाबत आपका क्या ख्याल है ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : It is good that the Minister of State for Food, Mr. Shinde is also here. He should also join with us; I do not know why he is sitting silently there. It is time that he also demands that more money should be given to the Food Corporation. We wanted that the banks should be nationalised so that the advantages may go to the general public and poor and middle class people. But as pointed out by Mr. Bhogendra Jha, the answers given tell us a very telling tale. After the banks were nationalised, more money has been given to the private dealers. It is indeed a very shocking matter. My specific questions are two. I would like to know, has the Government evolved a firm policy about the procurement of foodgrains, and can the Government say what are the essential items and percentage of those essential items of food grains like pulses, oilseeds, paddy, wheat and such other items which they

are going to procure completely by Food Corporation? As for myself I would like the important foodgrains to be procured by Food Corporation.

Sir, the present method of procurement by the Food Corporation is to be dependant on the middlemen and the millers. These people collect money from the banks and give to the millers and the millers procure for the Food Corporation. Of Rs. 200 crores which the Food Corporation is getting as a loan from the banks about 90% goes to the millers. So, it is not only Rs. 414 crores, as was mentioned by Mr. Shiv Chandra Jha—but Rs. 600 crores which goes to the private traders. Therefore, I would like to know what is the policy, whether a firm dead-line is given that at least essential crops and oilseeds would be purchased entirely through the Food Corporation and for that the Finance Ministry would also speak out what would be its policy to give credit. So far as I understand, it is the same old policy of disbursing which is still existing, and after nationalisation of banks there is no departure from the old policy of giving credit. I would like to know what would be the new policy of credit, how much percentage of credit or procurement of foodgrains is given to the private sector and how much to the public sector.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OE FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Sir, the discussion, as has been pointed out by the hon. Member, arises on account of the reply that was given by me with regard to the advances which were to be given by the banks to the Food Corporation.

Now, Sir, the position regarding advances to the Food Corporation is that about Rs. 238.5 crores is already advanced to the Food Corporation of India for procurement operations for the year 1970-71, and this is a Government loan which is again to be re-validated and this would continue to remain with the Food Corporation for their operations in the Fourth Plan period. Besides, there is ceiling of about Rs. 200 crores to be advanced by the State Bank and the Bank of Patiala–both inclusive—and now Allahabad Bank, Bank of India, Canara Bank, India Overseas Bank, Punjab National Bank, United Commercial Bank and United Bank of India have fixed a prime limit that will be taken over of about Rs. 25 crores. Therefore, as far as the availability of funds or money for the Food Corporation for its operations is concerned, there is no dearth of money and the Food Corporation will be able to take care of the purchases.

Here the policy of the Food Corporation, Sir, is two-fold—one to protect the interests of the producers, so that at the time of production they may not have to come and sell their foodgrains at low prices and the merchant may hoard and take the benefit. That is why the Food Corporation or the Government fixed up the purchasing prices with regard to the main commodities, particularly wheat which has been fixed at Rs. 76. Therefore the Food Corporation is taking care to ensure that the producers get reasonable prices and continue to have adequate incentives for increasing production and may not have to sell their stocks in the market at lower prices specially when production is good and the harvest is nice.

Secondly, to ensure that consumer prices are stabilised and the interests particularly of the low consumers are safeguarded, the issue prices have also been fixed by the Government. In the case of wheat the issue price is Rs. 78 and the margin with the Food Corporation is only Rs. 2. It is likely that on account of this issue price and purchase price, the Food Corporation may have to incur losses because the PL-480 foodgrains import is decreasing and the pool price benefit is not available. To that extent the prices get subsidised and that amount is likely to be a substantial amount as far as this year and the coming years are concerned; it would depend on the prices that we fix.

SHRI BHOGENDRA JHA: So, you are satisfied with the present prices of foodgrains in the country.

SHRI P. C. SETHI: As I have stated, our main objectives are two-fold: one is to protect the producer's interest and the second is to give the consumers better prices so that foodgrain prices may not soar up and he may not have to buy in the market at a higher price.

According to my information, prices of foodgrains between December 1969 and March 1970 have risen, but not, as the hon. Member has pointed out, substantially. There might have been some increase here or there; but that does not mean that prices of foodgrains have soared up.

SHRI BHOGENDRA JHA: Have you got the comparative figures of rice and paddy in December-January, 1968-69 and 1969-70?

SHRI P. C. SETHI: I do not have the comparable prices with me at the moment but according to my information between December 1969 and the end of March 1970 there has been no significant price increase for rice.

SHRI BHOGENDRA JHA: Before December there was no paddy crop; so, there cannot be any comparison between November and January. The comparison can only be with the prices of previous year.

SHRI P. C. SETHI: I do not have last year's figures with me.

As far as the Food Corporation is concerned the idea is to have a buffer stock of 5 million tonnes in the Fourth Plan period. Shri Kundu and Shri Shiva Chandra Jha wanted to know the actual stock. The actual stock with the Food Corporation at the moment is 3.5 million tonnes.

SHRI S. KUNDU: I was not at all interested in all these things. I wanted to know the credit policy after the nationalisation of banks.

SHRI BHOGENDRA JHA: These things we can know from Shri Shinde also; you are in Finance and from you we want to know the credit policy.

SHRI P. C. SETHI: The discussion which you have raised is so closely connected between Shri Shinde and myself that it matters very little whether he replies or I reply to it. That is why Shri Shinde is here to help me.

As I have pointed out, the Food Corporation is going to have a massive stock of 5 million tonnes in order to ensure that food prices do not rise and a proper price level is maintained.

A point has also been raised that the banking policy is not changed. This is not correct. Banks were advancing money but the overall availability will have to be looked at from the point of view as to for what productive purpose we should advance this money. For example, out of Rs. 3,000 crores which are likely to be the extra mobilisation of deposits during the Fourth Plan period, it is conceived that the banking sector would be able to advance about Rs. 400 crores to the agricultural sector from the commercial banks and Rs. 750 crores are likely to be advanced through cooperative banks. Therefore a substantial amount is likely to be advanced to the agricultural sector from the banking field. The total amount would be of the order of about Rs. 2,000 crores although, if the agricultural sector wants to take full advantage of it, the total requirement would be of the order of Rs. 4,000 crores. To that extent, it can be said, we will not be able to meet full requirements for the banking sector if the mobilisation remains at about Rs. 3,000 crores. But, at the same time, the policy is to advance money for all productive purposes and, as far as the trade is concerned, we are trying to restrict advances so that wherever there is any tendency for stocking or for hoarding or for any such type of activity, where the prices may soar high, that is checked. That is why, when it was noticed that advances were being given to the trade, the Reserve Bank tightened the policy and, instead of 35 per cent margin, they have increased to 50 per cent margin. On account of that, it has had a salutary effect on the advances. It is the policy of the Reserve

Bank, the State Bank and also of the commercial banks....

19 hrs.

SHRI BHOGENDRA JHA : Will you kindly let us know the amount proposed to be advanced or already advanced to the Food Corporation and the amount already advanced to the private trade in agricultural produce upto now or to be advanced hereafter? If you give it to the private trade, then the Food Corporation will be lagging behind.

SHRI P. C. SETHI : As I pointed out, we have put the figure at Rs. 200 crores for the commercial banks apart from the Government loan. What the Food Corporation has taken from the banks was hardly Rs. 4.5 crores as on 31st March 1970. As a matter of fact, the banks have approached us that a realistic figure of advances from the banks to the Food Corporation should be decided. When we have fixed the limit, that money has to be reserved for that purpose. Naturally, the Food Corporation is also increasing the work. There are about 26,000 employees in the Food Corporation and they are increasing the quantum of work. They are building up stocks; they are purchasing more and more foodgrains. Recently, the Food Minister informed me that in the case of oil, they have started purchasing soyabeans and they are also purchasing pulses besides other major foodgrains. It will depend upon the development of the Corporation and the situation existing and, from time to time, this will have to be done.

SHRI BHOGENDRA JHA : They do not want more from you.

SHRI P. C. SETHI : As I have indicated, we have got the State Bank and the Bank of Patiala has fixed a limit of Rs. 200 crores for such period, for example, in May, June and July, which are such months where their own requirement is more. Then, the State Bank and the Reserve Bank can also consider if more money is required, when the purchases are high, and we can increase the limit of Rs. 200 crores. It is not a sacrosanct limit that we will not cross the limit.

SHRI S. KUNDU : Why have you fixed the limit? Probably, Mr. Shinde does not want to cross the limit of Rs. 200 crores. Is it a conspiracy between the Finance Minister and the Food Minister to hoodwink the people because there is a limit of Rs. 200 crores, you cannot go beyond that and, therefore, you cannot procure any more?

SHRI P. C. SETHI : I would like Mr. Kundu to appreciate that in the banking operations, whenever you fix a limit for a particular Corporation or a particular sector in that case, that amount of money has to be kept reserved for that. Unless we know the actual utilisation, what can we do? As I pointed out, out of these Rs. 200 crores, the actual utilisation was of the order of Rs. 12 crores only. Where is the point of not providing money? I have said that if more money is required in those particular months, then, certainly, this limit is not so sacrosanct and it can also be increased. Besides, Rs. 25 crores have been promised by commercial banks already and Rs. 230 crores is a loan from the Central Government to the Food Corporation.

As far as the foodgrains, nationalisation and other points are concerned, I think, all this was debated during the Question Hour the other day and the hon. Food Minister replied very learly. The fact is there are about 1,38,000 fair price shops in the country through which we are distributing foodgrains at fair prices. Besides this, there is going to be a buffer stock and we are going to have curbs on the advances by the banks to these foodgrains traders. By extending the arm of the Food Corporation, naturally, we want to keep the prices under control and we also want to see that the prices do not soar high....

SHRI BHOGENDRA JHA : What is the mechanism?

SHRI P. C. SETHI : We are having the purchase price and the issue price. By that, we will be able to maintain the level of food

[Shri P. C. Sethi]
prices. Then, wherever there are scarcities, we will go in that particular area.......... (*Interruption*).

SHRI BHOGENDRA JHA : Are you going to withdraw the amount already advanced to the private trade by the nationalised banks?

SHRI P. C. SETHI : I have said that on account of the present position, we have already indicated that the Reserve Bank of India has issued certain curbs and restrictions on the advances to the traders. As far as this question of advances to the trade, to the industry and to the agriculture and other sectors is concerned, it cannot be a rigid policy. It will to be flexible according to the needs of the economy and the requirements of the trade. From this point of view we will certainly take into account the requirements of the agricultural sector. Certainly it should be given priority. That is being given.

SHRI RANDHIR SINGH : What about my specific question?

SHRI P. C. SETHI : As far as Ch. Randhir Singh's particular question is concerned regarding purchase of foodgrains, purchase of foodgrains is done in consultation with the State Government according to the policy that is decided by them and wherever the mandis and places they point out, the Food Corporation is fully co-operating with the State Governments and it is with their policy decision that the Food Corporation goes in for purchase.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : Let him persuade Haryana Government to allow the Food Corporation to operate in Haryana.

SHRI RANDHIR SINGH : My Government is always co-operating. I want to know whether you have done something in the matter. (*Interruptions.*) It is an all-India issue. It is not only for Haryana. The Food Corporation is the grain bank of India.

SHRI P. C. SETHI : If the hon. Member is pleased, he can certainly call the Food Corporation the grain bank of India. There is no harm.

As far as the Credit Corporation is concerned, the nationalised banks, the co-operative sector and other sectors would be giving more loans to the agricultural sector. Therefore, there is no particular need at the moment to consider this.

SHRI RANDHIR SINGH: Why no need? You give to Birlas and Tatas. You cannot give to farmers. What is this? We cannot accept it.

बिड़ला और टाटा जैसों के लिए तो आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन गरीब किसानों के लिए कुछ भी नहीं है ? गरीब किसानों के लिए क्रेडिट कारपोरेशन कर दो ताकि वे वहां जा कर कर्ज ले लें और जो कुछ उनके पास है वह आप ले लो ।

This is something which touches our sentiments?

What is the harm in giving credit to agriculture which is the biggest industry in the country?

SHRI BHOGENDRA JHA : He is evading the point. Why such large amounts are given to the private trade? What is the remedy for that?

SHRI P. C. SETHI : As far as the advances to agricultural sector are concerned, Choudhry Sahib should appreciate this point that the very purpose of nationalising the banks was to take care of such sections of the society which were not taken care of earlier. That is why the nationalised banks are going to open more branches in the rural areas. Out of 1200 branches which are going to be opened this year, 750 are going to be in the rural sector with the result that the rural

sector will be taken care of. I am not adverse to the suggestion. I appreciate the suggestion made by the hon. Member and if there is anything like that that if the present advances which are being given to the farmers are not found sufficient and if there is any demand, certainly Government will look into that.

SHRI RANDHIR SINGH : Why is this discrimination ?

SHRI P. C. SETHI : Where is the discrimination ?

As far as nationalisation of foodgrains trade is concerned, I have stated the point that already the Food Corporation's activities are expanding. The Food Minister has explained the situation the other day. I need not go into that point again.

Sir, I think I have met all the points made.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday.

19.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 20, 1970/Chaitra 30, 1892 (Saka.)

Tej Kumar Press, Lucknow. 17-6-70